शोध मंथन Vol. XIV No.IV Oct.-Dec. 2023 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 8.870 (SJIF)

# उच्च शिक्षा : समस्या एवं समाधान

प्राप्तिः 09.11.2023
स्वीकृतः 22.12.2023

**डॉ० सुमिता शर्मा**
प्रभारी एवं एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विभाग
एन०के०बी०एम०जी०(पी०जी०) कॉलेज, चन्दौसी (सम्भल)
एम०जे०पी० रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
ईमेलः *sumitasharma.246@gmail.com*

77

***सारांश***

*समाज व देश की प्रगति के लिए मानवीय संसाधनों को विकसित करना आवश्यक होता है। यह महत्वपूर्ण कार्य शिक्षा द्वारा ही सम्भव हो सकता है। मानवीय संसाधनों के विकास की दृष्टि से प्रत्येक स्तर पर शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है परन्तु वर्तमान समय में शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय है। अतः शिक्षा व्यवस्था में सुधार की अनिवार्यता को नकारा नहीं जा सकता। वैसे तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च सभी स्तरों पर है लेकिन इनमें भी मुख्य रूप से शिक्षा के उच्च स्तर पर सुधार अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि उच्च शिक्षा ही समस्त तकनीकी अविष्कारों, उच्च रोजगारों, समस्त विकास एवं प्रगति की जननी है। उच्च शिक्षा किसी भी देश की न केवल आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होती है बल्कि वह उसके सामाजिक चिंतन की बुनियाद, सांस्कृतिक बनावट की समझ और राजनीतिक प्रतिष्ठा की परिचायक होती है। हमारे यहाँ उच्च शिक्षा के स्तर में आमूल–चूल परिवर्तन की नितांत आवश्यकता है क्योंकि हमारी शिक्षा में न केवल ब्रिटिश कालीन अधिकांश दोष अभी तक विद्यमान है, अपितु उच्च शिक्षा से सम्बन्धित बहुत सी समस्यायें उत्पन्न हो गई है; जैसे उच्च शिक्षा की उद्देश्य–हीनता, प्रवेश सम्बन्धी समस्यायें, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम व परीक्षा प्रणाली, निर्देशन एवं परामर्श का अभाव, शिक्षा का निम्न स्तर आदि। इन समस्याओं के समाधान द्वारा उच्च शिक्षा को प्राथमिकता के आधार पर दुरस्त कर ही हम भारत को विकसित देश की श्रेणी में खड़ा कर सकते हैं।*

***मुख्य बिन्दु***

*उच्च शिक्षा, समस्या, उद्देश्यहीनता, प्रवेश, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, निर्देशन एवं परामर्श, समाधान।*

उच्च शिक्षा का अभिप्राय है शैक्षिक रचना के विभिन्न स्तरों में सबसे ऊँचे स्तर की शिक्षा। उच्च शिक्षा को विश्वविद्यालयी शिक्षा भी कहा जाता है क्योंकि शैक्षिक पिरामिड में विश्वविद्यालय सबसे ऊपर आते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालय को परिभाषित करते हुए कहा है कि "विश्वविद्यालय वह स्थान है जहाँ पर सब अपने–अपने योगदान द्वारा सत्य की खोज करते हैं और अपनी शैक्षिक उन्नति द्वारा व्यक्तित्व का विकास करते हैं।" किसी भी देश की सम्पन्नता या भाग्य उस देश के विश्वविद्यालयों से जुड़ा होता है। अतः राष्ट्र की प्रगति में विश्वविद्यालयों का महत्वपूर्ण

योग रहता है। विश्वविद्यालय सांस्कृतिक जीवन के केन्द्र एवं समाज के पुनरूत्थान में अग्रणी होते हैं। सामाजिक मूल्यों का निर्माण और उनकी रक्षा करना इनका परम कर्त्तव्य है साथ ही यह राजनैतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्र के मार्ग–दर्शक होते हैं क्योंकि इन्हीं से निकलकर विद्यार्थी समाज का नेतृत्व करते हैं और इनके हाथ में ही सरकार की बागडोर होती है। अतएव प्रत्येक देश उच्च शिक्षा के प्रति सजग रहता है। भारतीय विश्वविद्यालयों के ऊपर तो एक विशेष दायित्व है और वह है सामाजिक और सांस्कृतिक पुर्ननिर्माण। वास्तव में उच्च शिक्षा शिक्षा का वह स्तर है जो देश को प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करता है।

हमारे देश में उच्च शिक्षा की शुरूवात वैदिक काल में हो चुकी थी तब उच्च शिक्षा से तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा के बाद गुरूकुलीय शिक्षा से था। प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा में कई केन्द्र भी थे परन्तु भारत में आधुनिक उच्च शिक्षा का श्री गणेश यूरोपीय ईसाई मिशनरियों द्वारा हुआ। आज हमारे देश में विश्वविद्यालयी शिक्षा का स्वरूप अंग्रेजी शासन की देन है। भारत का उच्च शिक्षा तंत्र अमेरिका चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे उच्च शिक्षा तंत्र है। सभी को शिक्षा के समान अवसर सुलभ कराने की नीति के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश में महाविद्यालयों और विद्यालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साथ ही उच्च शिक्षा की सुविधाओं पर विनियोग भी तद्नुरूप बढ़ा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इसके बावजूद भी उच्च शिक्षा की सुलभता का सपना साकार नहीं हो पा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं हुई है। हाल ही में जारी विश्वविद्यालय रैकिंग में विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में एक भी भारतीय विश्वविद्यालय को स्थान प्राप्त नहीं हो सका है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् के शोध के अनुसार भारत के 90% और 70% विश्वविद्यालयों का स्तर बहुत ही कमजोर है। हाल ही में नैसकॉम और मैकिन्से द्वारा किये गए शोध के अनुसार मानविकी विषयों में 10 में से 01 और इंजीनियरिंग में डिग्री ले चुके 4 में से 1 भारतीय छात्र ही नौकरी पाने योग्य पाए गए हैं। हालांकि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी और वैज्ञानिक मानव शक्ति का खजाना है इस तथ्य पर यहीं प्रश्न चिन्ह लग जाता है।

उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में एक विशेष बात यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् उसका संख्यात्मक विकास अत्यन्त त्वरित गति से हुआ है। साथ ही, दूसरी विशेष बात यह है कि उसका विकास आदि से अन्त तक अनियोजित रहा है। परिणामतः शिक्षा का स्तर गिर गया है। छात्रों में ज्ञानार्जन की अभिलाषा नष्ट हो गई है। शिक्षित व्यक्तियों के समक्ष बेरोजगारी की समस्या उपस्थित हो गई है और सर्वोपरि यह शिक्षा देश की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ हो गई है। अतः जैसा कि कोठारी कमीशन ने लिखा है– "भारत में सामान्य भावना यह है कि उच्च शिक्षा की स्थिति असन्तोषजनक एवं भयप्रद है।" उच्च शिक्षा के प्रति इस सामान्य भावना का कारण है उसमें परिलक्षित होने वाली बहुरंगी समस्यायें।

भारत की उच्च शिक्षा भी माध्यमिक शिक्षा के समान उद्देश्य विहीन है। यह शिक्षा विद्यार्थी को जीविकोपार्जन के लिये तैयार नहीं करती। यह उन्हें केवल पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करती है। यही कारण है कि बी0ए0, एम0ए0 पास करने के उपरान्त बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी बेकार रहते हैं। उनके पास कोई ऐसा कौशल नहीं होता जिससे वे अपना तथा अपने परिवार का भरण–पोषण कर सकें। उच्च शिक्षा के उद्देश्यहीन एवं अव्यवहारिक होने के कारण अधिकांश विद्यार्थी क्लर्की या स्टोरकीपरी अथवा कोई छोटा–मोटा पद धारण करने पर विवश हो जाते हैं। परिणामस्वरूप बहुत से

विद्यार्थियों की योग्यता, कुशलता एवं विशेष गुणों के लाभों से देश वंचित रह जाता है। उच्च शिक्षा का केवल एक ही उद्देश्य है– विश्वविद्यालय की उपाधि से अलंकृत होकर कोई सरकारी या गैरसरकारी नौकरी प्राप्त करना। अतः हमारे विश्वविद्यालयों की उद्देश्यहीन शिक्षा हमारे देश एवं नवयुवकों के जीवन पर कुठाराघात कर रही है। विश्वविद्यालयों की सोद्देश्य शिक्षा ही राष्ट्र के वैभव और उनके निवासियों की बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिकता श्रेष्ठता की निर्धारण शक्ति है। आधुनिक भारत की आवश्यकता है वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का प्रसार, विभिन्न क्षेत्रों में स्तरीय अनुसंधान, व्यवसायपरक शिक्षा, नूतन ज्ञान की खोज, उत्पादन में वृद्धि, व्यवसायिक दक्षता, राष्ट्रीय एकीकरण आदि उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली उच्च शिक्षा। इसका उद्देश्य मात्र डिग्री प्राप्त करना नहीं वरन् इसका उद्देश्य आवश्यकतानुसार मानवी संसाधनों को तैयार करना है। उच्च शिक्षा के द्वार प्रतिभा सम्पन्न एवं विषयगत रूचि रखने वाले जिज्ञासु छात्रों के लिये सदैव खुले रहने चाहिये। 'कार्डिनल न्यूमैन' ने लिखा है "यदि विश्वविद्यालयों की शिक्षा का कोई व्यवहारिक उद्देश्य है तो मैं कह सकता हूँ कि वह समाज के उत्तम नागरिकों को प्रशिक्षित करना।"

आज भारतीय विश्वविद्यालयों एवं उससे सम्बद्ध कॉलेजों में प्रवेश की कठिनाइयाँ भी बढ़ती जा रहीं हैं। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रवेशार्थियों की भीड़ निरन्तर बढ़ रही है। यह भीड़ यदि ज्ञान पिपासुओं की होती है तो देश का सौभाग्य होता। दुख यह है कि उच्च शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नौकरी पाने के लिये डिग्री हासिल करना रह गया है। सामान्यतः पिछली परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर या प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश दे दिया जाता है परन्तु सीमित स्थान माध्यमिक शिक्षा का विस्तार एवं साथ ही विशेष रूप से क्षेत्र, जाति, धर्म, एवं लिंग के आधार पर आरक्षण के कारण अधिकांश छात्रों को प्रवेश नहीं मिल पाता। आरक्षण की प्रक्रिया के कारण प्रायः प्रतिभाशाली छात्र प्रवेश पाने से वंचित रह जाते हैं और समाज के कम प्रतिभा वाले छात्रों को प्रवेश मिल जाता है। उच्च शिक्षा के लिये यह बहुत बड़ा अभिशाप है। अतः छात्रों के प्रवेश दबाब को नियन्त्रित करने के लिये उच्च शिक्षण संस्थाओं में उच्च अध्ययन एवं अनुसंधान कार्य में रूचि लेने वाले एवं प्रतिभाशाली छात्रों को ही प्रवेश दिया जाये। माध्यमिक शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाये। मुक्त प्रवेश नीति के स्थान पर चयनात्मक प्रवेश नीति को अपनाया जाये। क्षेत्र, जाति, धर्म के आधार पर आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था को बन्द कर दिया जाये। प्रवेश में निश्चित नियम निर्धारित किये जाये जैसे–आयु, परीक्षा के प्राप्तांक, साक्षात्कार, प्रगति पत्र आदि।

उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम सैद्धान्तिक, साहित्यिक, नीरस, संकीर्ण, परम्परागत, बोझिल विषय केन्द्रित, नितान्त औपचारिक है। यह समाज की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं तथा भावनाओं के अनुकूल नहीं है। वर्तमान विकासवादी युग में इसका योगदान नगण्य है। छात्रों की रूचि एवं मनोवृत्ति के अनुकूल नहीं है, इसमें कार्यानुभव को स्थान नहीं दिया गया है। जीवन की व्यवहारिकता का अभाव है। देशकाल की परिस्थितियों से उसका कोई तालमेल नहीं है। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप निर्मित किये जायें। कार्यानुभव पर आधारित एवं व्यवसायपरक हों। पाठ्यक्रम में सैद्धान्तिक ज्ञान को वास्तविक ज्ञान से जोड़ा जाये। सामान्य विशिष्ट एवं आनर्स पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए। पाठ्यक्रम निर्मित करते समय छात्रों की रूचि योग्यता और उनके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखना चाहिए जिससे उन्हें वास्तविक जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सके। परिस्थितियों के अनुसार पाठ्यक्रम में संशोधन की गुजांइश होनी चाहिए जिससे उसका पुनर्निरीक्षण कर उसे अद्यतन बनाया जा सके।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का मानना है कि "यदि हम विश्वविद्यालय शिक्षा के केवल एक विषय में सुधार का सुझाव दें तो यह परीक्षाओं के सम्बन्ध में होना चाहिए।" कोठारी कमीशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, नई शिक्षा नीति 1986 और उसके बाद बनी समितियों ने भी परीक्षा सम्बन्धी दोषों पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है और उनको दूर करने पर बल दिया है। उच्च शिक्षा में परीक्षायें ही सर्वोपरि हैं। सम्पूर्ण शिक्षण परीक्षाओं के अधीन है। वर्तमान शिक्षा पद्धति इतनी दोषपूर्ण है कि उससे सही मूल्यांकन की आशा नहीं की जा सकती। आधुनिक परीक्षाओं में विश्वसनीयता व वैद्यता का अभाव है। इस पद्धति में विद्यार्थी की स्मरण शक्ति एवं लेखन गति का ही परीक्षण किया जाता है। उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा दोष प्रचलित परीक्षा प्रणाली है। यह छात्रों के ज्ञान का उचित माप नहीं करतीं उसे रटने एवं अनुचित साधनों के प्रयोग के लिये बाध्य करती है। अतः वर्तमान परीक्षा पद्धति में सुधार अपेक्षित है। परीक्षाओं को अधिकाधिक वैज्ञानिक विश्वसनीय एवं वैध बनाने की आवश्यकता है। इस दिशा में शोध कार्य किये जायें। छात्रों का अनवरत् मूल्यांकन किया जाये। आंतरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया को सर्वाधिक महत्व दिया जाये। लिखित व मौखिक व प्रयोगात्मक परीक्षाओं का सम्पादन व मूल्यांकन पूरी ईमानदारी व परिश्रम व गंभीरता से किया जाये। परीक्षाओं में अंक देने की बजाये सप्त बिन्दु मापनी (सेविन प्वांइट स्केल) पर ग्रेड दिये जाये। गैस पेपर्स, गाइड, प्रश्नोत्तरी, सरल अध्ययन आदि पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाया जाये और पाठ्यपुस्तकों का अध्ययन करने के लिये छात्रों को प्रोत्साहित किया जाये।

भारतीय उच्च शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थियों को निर्देशन और उचित परामर्श देने का कोई प्रबन्ध नहीं किया जाता। अतः छात्र अपनी स्वयं की इच्छा, अभिभावकों के दबाब या किसी अनुभवहीन मित्रों या व्यक्ति के परामर्श से पाठ्यविषयों का चयन कर लेते हैं। इस प्रकार का चयन अनेक छात्रों के समक्ष संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर देता है। पाठ्य विषयों का थोड़ा सा अध्ययन ही उनको स्पष्ट संकेत देने लगता है कि वे उनकी रूचियों, क्षमता और भावी जीवन की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है, जिसका दुष्परिणाम है परीक्षा एवं जीवन में असफलता। अतः छात्रों की भावी सफलता एवं सम्पन्नता के लिये परम आवश्यक है कि निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं को उच्च शिक्षा का अविभाज्य अंग बनाया जाये। ये सेवायें ही छात्रों की रूचियों, क्षमताओं, आवश्यकताओं व शैक्षिक योग्यताओं का अध्ययन करके उसे उपर्युक्त व उपयोगी पाठ्यविषयों का चयन करने में सहायता दे सकती हैं। इन सेवाओं को अनिवार्य बताते हुए कोठारी कमीशन ने लिखा है– "निर्देशन एवं परामर्श का कार्यक्रम जो छात्रों को पाठ्यक्रमों का चयन करने और उनकी संवेगात्मक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं को सुलझाने में सहायता देता है उच्च शिक्षा का अभिन्न अंग होना चाहिए।"

आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हम शिक्षा के क्षेत्र में अपनी जरूरतों के अनुसार जागरूकता व शक्ति नहीं ला पाये है। इसका मुख्य कारण उच्च शिक्षा पर लगातार घटता सरकारी खर्च, रिक्त पद, जीवन मूल्यों का अभाव, विषय में पारंगत शिक्षकों का अभाव व निम्न स्तर के संस्थान है। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा से सम्बन्धित अन्य बहुत सी समस्यायें–छात्र अनुशासनहीनता, अपव्यय एवं अवरोधन, शिक्षा में विशिष्टीकरण, शिक्षा का माध्यम, छात्र संख्या में वृद्धि, शिक्षा का निम्न स्तर, व्यवसायिक व तकनीकी शिक्षा का अभाव, वित्त समस्या, शोध कार्यों का अभाव, प्रशासनिक समस्याएं, प्रतिभा पलायन आदि हैं जिनका समाधान अत्यन्त आवश्यक है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमें सर्वप्रथम उन समस्याओं को हल करना चाहिए जिनके कारण यह अर्थहीन हो गई है। किसी भी समस्या को हल करने के लिए वो साधन चाहिए–एक वित्तीय

संसाधन और दूसरा कार्यरत व्यक्तियों की ईमानदारी और कर्त्तव्यनिष्ठता। यदि सरकार उच्च शिक्षा की उचित व्यवस्था के लिए पर्याप्त धनराशि जुटा दे और उच्च शिक्षा से जुड़े सभी व्यक्ति ईमानदारी और कर्त्तव्य निष्ठता के साथ कार्य करे तो काफी कुछ सीमा तक जंग को जीता जा सकता है। वास्तव में शिक्षा का उन्नयन तभी सम्भव है जबकि हम सभी उसके सुधार के सम्बन्ध में दृढ़ संकल्पित हो। इस संदर्भ में हमें जोसेफ स्टीलन ने इस कथन पर भी अनिवार्य रूप से ध्यान देना होगा कि "शिक्षा वह हथियार है जिसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कौन दे रहा है और किसे दे रहा है।"

## संदर्भ

1. पचौरी, डॉ० गिरीश. भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास. विनय रखेजा आर0 लाल बुक डिपोः मेरठ।
2. सारस्वत, डॉ० मालती., गौतम, प्रो० एस.एल. भारतीय शिक्षा का विकास एवं सामयिक समस्यायें. आलोक प्रकाशनः लखनऊ।
3. श्रीवास्तव, रमाकान्त. भारतीय शिक्षा. गर्ग–ब्रदर्स, कटरा रोडः प्रयाग।
4. लाल, रमन बिहारी. भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं समस्यायें. रस्तौगी पब्लिकेशन, गंगोत्री शिवाजी रोडः मेरठ।
5. शर्मा, डॉ० नमिता., पाराशर, डॉ० मधु., शर्मा, पल्लवी., सिंह, दीपा. शिक्षा का वैचारिक ढाँचा. एस.बी.पी.डी. पब्लिकेशनः आगरा।
6. पाठक, पी०डी०. भारतीय शिक्षा और उसकी समस्यायें. विनोद पुस्तक मंदिरः आगरा।
7. शर्मा, बी०डी०. भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास. ओमेगा पब्लिकेशन्सः नई दिल्ली।
8. शर्मा, डॉ० ए०पी०. भारतीय शिक्षा की समस्यायें. अशोक पब्लिशिंग हाउसः गांधी नगर, मेरठ।
9. त्यागी, गुरूसरन दास. भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास. अग्रवाल पब्लिकेशन्सः आगरा।
10. भार्गव, डॉ० विवेक. (सं०). शिक्षामित्र त्रैमासिक पत्रिका. कचहरी घाट, आगरा।